प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 25 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 19 – 26 जून 2017 मूल्य पांच रूपए

भ्रष्टाचार के प्रकरण में

वीरभद्र की विजिलैन्स की सक्रियता और भाजपा की अस्पष्टता क्या रंग दिखायेगी

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के चुनावों के बाद जहां भाजपा ने सत्ता परिवर्तन के लिये रथ यात्राएं शुरू की हैं वहीं पर वीरभद्र की विजिलैन्स ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा की रथ यात्रा में वीरभद्र सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर जनता को जागृत किया जा रहा है। उधर विजिलैन्स ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। एक एफआईआर धूमल शासन में खरीदी गयी एंटी हेलगन मामले में है तो दूसरी आईपीएच की गिरी वॉटर स्पलाई योजना को लेकर है। इन दोनों मामलों में विजिलैन्स को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति अभी निगम चुनावों के दौरान ही दी गयी है। स्वभाविक है कि यह अनुमतियां दिये जाने से पहले यह मामले मुख्यमन्त्री और उनके सचिवालय के संज्ञान में लाये गये होंगे क्योंकि गृह और सतर्कता का कार्यभार भी मुख्यमन्त्री के अपने ही पास है। यह मामले कांग्रेस के आरोप पत्र में दर्ज रहे हैं और आरोप पत्र विजिलैन्स को जांच के लिये भी सत्ता संभालने के बाद हुई पहली मन्त्रीमण्डल की बैठक में भेजने का निर्णय ले लिया गया था। ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि यह मामले अभी क्यों दर्ज हुए और क्या इनके अन्तिम परिणाम अभी आ पायेंगे? ऐसी संभावना कम है क्योंकि अब तक जिन मामलों पर विजिलैन्स का ध्यान केन्द्रित रहा है उनमें ही कोई परिणाम सामने नही आये हैं। ऐसे में इन नये मामलों को चुनावी रणनीति के आईने में ही देखा जायेगा। कांग्रेस और वीरभद्र सरकार की इस रणनीति के क्या परिणाम होंगे इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गये हैं, क्योंकि निगम चुनावों में मिली हार का ठीकरा वीरभद्र और सुक्खु ने खुलकर एक दूसरे के सिर फोड़ा है।

दूसरी ओर भाजपा अपनी रथ यात्रा में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर जनता से सत्ता परिवर्तन का आग्रह कर रही है। भाजपा का सारा शीर्ष नेतृत्व शान्ता से लेकर नड्डा तक वीरभद्र सरकार को भ्रष्टाचार का पर्याय प्रचारित कर रहा है। सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाये जा रहे हैं। वीरभद्र सीबीआई से जमानत पर चल रहे है और उनका अधिकांश समय अदालतों में केसों के प्रबन्धन में व्यतीत हो रहा है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिस मुख्यमन्त्री का ज्यादा वक्त अदालतों में गुजर रहा है उसके पास प्रदेश के विकास के बारे में सोचने का समय ही कहां बचा है। आम आदमी को थोड़े समय के लिये प्रभावित करने में इस प्रचार से लाभ मिल सकता है लेकिन जब इसी तस्वीर का दूसरा चेहरा जनता के सामने आयेगा तो स्थिति एकदम दूसरी हो जायेगी। क्योंकि यह सही है कि वीरभद्र केन्द्र की जांच ऐजैन्सीयों द्वारा बनाये गये मामलों में उलझे हुए हैं और इन मामलों के अन्तिम परिणाम नुकसानदेह भी हो सकते है। परन्तु बड़ा सवाल तो यह है कि अन्तिम परिणाम आयेगा कब? सीबीआई मामलें में वीरभद्र सहित सारे नामज़द अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। इस मामले में राजनीतिक लाभ मिलना संभव नही है। सीबीआई मामले को अदालत से अन्जाम तक पहुंचाने में समय लगेगा। सीबीआई के साथ ईडी में चल रहे मनीलॉड्रिंग प्रकरण में ऐजैन्सी ने 23 मार्च 2016 को पहला अटैचमैन्ट आर्डर जारी किया और करीब आठ करोड़ की चल/अचल संपत्ति अटैच की। इसके बाद जुलाई में वीरभद्र सिंह के एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान की गिरफ्तारी हुई जो अब तक चल रही है। इस गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने एक और अटैचमैन्ट आदेश जारी किया है लेकिन इस पर कोई गिरफ्तारी नही हुई है। बल्कि अब जो तिलकराज प्रकरण हुआ है वह भी ईडी में जा पहुंचा है। तिलक राज और अशोक राणा गिरफ्तार चल रहे हैं। परन्तु उससे आगे कुछ नही हुआ है और यह न होना ही सारे प्रकरण को राजनीतिक द्वेष का रंग दे रहा है।

ईडी पर अदालत की ओर से कोई रोक नहीं है। तिलकराज प्रकरण में सूत्रों के मुताबिक जो पैसा लिया जा रहा था वह वास्तव में ही मुख्यमन्त्री के ओएसडी रघुवंशी तक जाना था। उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एक बडे को 1.85 करोड़ की अदायगी की जानी थी। इसमें 1.50 करोड़ का प्रबन्ध शिमला में बैठे प्रबन्धकों ने कर लिया था। शेष 35 लाख तिलकराज ने जुटाना था और उसी के जुगाड़ में तिलकराज सीबीआई के ट्रैप का शिकार हो गया। चर्चा है कि इस ट्रैप के पिछले दिन ही चण्डीगढ़ के एक हितैषी ने जिससे सुभाष आहलूवालिया के प्रकरण में ईडी कभी कुछ पुछताछ भी कर चुकी है उसने बद्दी जाकर तिलकराज सहित ड्रग और पाल्यूशन के बड़ो को भी सचेत किया था कि किसी के भी खिलाफ कभी भी बड़ी कारवाई हो सकती है और दूसरे ही दिन यह घट गया। इसी तरह यह भी चर्चा है कि जब ईडी ने मई में वीरभद्र को रात करीब दस बजे तक पूछताछ के लिये रोका था उस दिन भी भाजपा के एक बड़े नेता के ईशारे पर बड़ी कारवाई को रोक दिया गया था। चर्चा है कि इस बड़े नेता ने अरूण जेटली के समाने यह रखा है कि यदि वीरभद्र के खिलाफ बड़ी कारवाई को अन्जाम दिया जाता है तो भाजपा को इससे प्रदेश के चुनावों में 25 सीटों का नुकसान हो सकता है। भाजपा के इस बड़े नेता की यह आशंका नगर निगम के चुनावों में सही भी सिद्ध हुई है। क्योंकि इतने बडे चूनावी प्रचार के वाबजूद भाजपा को परिणामों में स्पष्ट बहुमत नही मिल पाया। वीरभद्र और सुक्खु के टकराव के परिणामस्वरूप कांग्रेस चुनाव में कहीं नजर ही नही आ रही थी। इतनी सफलता भी वीरभद्र के व्यक्तिगत प्रयासों से ही मिली है। ऐसे में आने वाले दिनों में वीरभद्र की विजिलैन्स की सक्रियता और वीरभद्र मामले में भाजपा की अस्पष्टता क्या रंग दिखाती है। इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।

क्या बड़े बाबूओं के हितों के टकराव के कारण नहीं भरे जा रहे रेगुलैटरी कमीशन और ट्रिब्यूनल के खाली पद

शिमला/शैल। प्रदेश का शिक्षा के लिये गठित रेगुलेटरी कमीशन एक वर्ष से भी अधिक समय से खाली चला आ रहा है। प्रदेश में पिछले छः महीने से ही कोई लोकायुक्त भी नही है। पिछले दिनो प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक सदस्य का खाली हुआ पद भी अभी तक भरा नहीं गया है। यह सारे संस्थान महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और इनका इस तरह खाली रहना न केवल इनकी अहमियत को ठेस पहुंचाता है बल्कि सरकार और उसके शीर्ष प्रशासन की नीयत और नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। रेगुलेटरी कमीशन और प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सरकार के मौजूदा या सेवानिवृत हो चुके बड़े बाबूओं में से ही किसी की तैनाती होनी है। इन पदों के लिये दर्जनों बाबुओं ने दावेदारी भी पेश कर रखी है। लोकायुक्त के पद पर किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत मुख्य न्यायधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का भी ऐसा ही कोई न्यायधीश नियुक्त होना है। चर्चा है कि इस पद के लिये अन्यों के अतिरिक्त प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायधीश मंसूर अहमद मीर और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायधीश टी एस ठाकुर भी दावेदार हैं। इन दोनों के ही मुख्यमन्त्री के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। संभवतः इन्ही संबंधो के कारण यह चयन कठिन हो गया है।

लेकिन रेगुलेटरी कमीशन और प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में नियुक्तियां क्यों नही हो पा रही हैं इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं उठनी शुरू हो गयी हैं। इस समय वीसी फारखा की बतौर मुख्यसचिव पदोन्नति और तैनाती को उनसे वरिष्ठ विनित चौधरी ने कैट में चुनौती दे रखी है। इसमें अभी प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार से जवाब दायर होने हैं। माना जा रहा है कि इस समय केन्द्र सरकार में सचिव कार्मिक का पदभार अजय मित्तल के पास आ गया है और मित्तल हिमाचल कार्डर से ही ताल्लुक रखते हैं इसलिये अब केन्द्र सरकार से जवाब आने में ज्यादा समय नही लगेगा। बल्कि फारखा के बाद तरूण श्रीधर दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं और केन्द्र के सचिव पैनल में आ गये है। मुख्यमन्त्री ने उनके दिल्ली जाने को भी हरी झण्डी दे दी है। परन्तु विनित चौधरी की याचिका में फारखा से ज्यादा तरूण श्रीधर की भूमिका पर सवाल खड़े किये गये हैं। संभवतः इन्ही सवालों के साथ उनके केन्द्र में सचिव पद के चयन पर भी सवाल उठाये गये हैं और इन सवालों पर राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है। इस परिदृश्य में फारखा और श्रीधर दोनों ही अधिकारियों के रेगुलेटरी कमीशन या ट्रिब्यूनल में जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि अभी दोनों की नौकरी काफी शेष है। फिर फारखा को मुख्यमन्त्री भी छोड़ना नही चाहेंगे। लेकिन कल को विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही इलैक्शन कोड लागू होने पर यदि उनके मुख्य सचिव रहने पर चुनाव आयोग में आपत्ति उठा दी जाती है तो उस स्थिति में एकदम सारा परिदृश्य बदल जायेगा। लेकिन इस स्थिति को आने में अभी दो तीन माह का समय लग जायेगा।

ऐसे में यह सवाल सचिवालय के गलियारों की चर्चा बना हुआ है कि अभी निकट भविष्य में इन पदों को भरे जाने की संभावना नही है। परन्तु इसी के साथ यह भी चर्चित हो रहा है कि यदि कोड ऑफ कन्डक्ट लागू होने तक यह पद नही भरे जाते हैं तो फिर यह नियुक्तियां नई सरकार के गठन के बाद ही हो पायेंगी। मजे की बात यह है कि इन अहम पदों के खाली चले आने पर विपक्ष की ओर से भी कोई सवाल नही उठाये जा रहें हैं। रेगुलेटरी कमीशन में मुख्यमन्त्री के प्रधान निजि सचिव सुभाष आहलूवालिया की पत्नी मीरा वालिया ने प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत होकर बतौर सदस्य ज्वाईन किया था लेकिन जैसे ही लोक सेवा आयोग में सदस्य का पद खाली हुआ तो मीरा वालिया ने रेगुलेटरी कमीशन से त्यागपत्र देकर लोकसेवा आयोग में जिम्मेदारी संभाल ली। अब रेगुलैटरी कमीशन बिल्कुल खाली हो गया है। इन पदों को समय पर भरने के लिये और सारी स्थिति को मुख्यमन्त्री के संज्ञान में लाने की जिम्मेदारी मुख्यमन्त्री के अपने ही कार्यालय की होती है, परन्तु मुख्यमन्त्री के कार्यालय पर तो सेवानिवृत अधिकारियों का कब्जा है। उन्होने चुनाव लड़कर जनता से वोट मांगने तो जाना नही है। फिर ऐसे पदों के इतने लम्बे समय तक खाली रहने से सरकार की जनता में छवि पर क्या असर पड़ता है इससे उनको कोई सरोकार कैसे हो सकता है। माना जा रहा है कि बड़े बाबूओं के हितों में चल रहे टकराव के कारण अभी यह पद भरे जाने की कोई संभावना नही है।

मंत्रिमंडल के निर्णय

आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति तैयार करने की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में आउटसोर्स कर्मियों को आशा प्रदान करते हुए सेवा प्रदात्ताओं के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर तैनात आउटसोर्स कर्मियों की कार्य स्थिति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीति निर्देश बनाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट सत्र 2017-18 में विधानसभा सदन में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति तैयार करने की घोषणा के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायकों के 75 पद भरने के निर्णय के अतिरिक्त 31 मार्च, 2017 को अनुबंध आधार पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले 533 पंचायत सचिवों को नियमित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 31 मार्च, 2017 को तीन साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले 179 पंचायत सहायकों के पदनाम परिवर्तित कर उन्हें अनुबंध आधार पर पंचायत सचिव बनाने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में युद्ध विधवाओं के बेटियों की वित्तीय सहायता 15000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये करने तथा एक्शन या ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए सेना तथा अर्धसैनिक बलों में के आश्रितों की अनुग्रह राशि में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। सेना तथा अर्ध-सैनिक बलों में युद्ध में शहीद होने पर 20 लाख रुपये, घायल होने पर 5 लाख रुपये तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में 2.50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को पूर्ण करते हुए पदों के सृजन सहित परवाणु के अंबोटा, बरोटीवाला, पावंटा साहिब के सतौन, गगरेट तथा भोरंज में नए ईटीओ सर्कल खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के कर्मियों तथा पेंशनभोगियों को उनके विकल्प के अनुसार स्थाई चिकित्सा भत्ते को 1 जून, 2017 से 350 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति माह करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में 51 हजार कर्मी तथा 29 हजार पेंशनभोगी हैं। इस निर्णय से राज्यकोष पर वार्षिक 4.80 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

मंत्रिमण्डल ने कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से जेबीटी के लिये निर्धारित 15 प्रतिशत पदोन्नति कोटे से टीजीटी (मेडिकल) के 348 रिक्त पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में बिलासपुर जिला के बंदला स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन, तकनीकी तथा मिनिस्ट्रियल स्टॉफ के 125 पद सृजित करने व भरने को स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, सोसायटी को अन्य आवश्यक पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 57 पद तथा कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल) के तीन पद भरने को भी स्वीकृति दी।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग में डेंटल मैकेनिकस् के 50 पद भरने को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक में मत्स्य पालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

स्वास्थ्य सुरक्षा तथा विनियमन विभाग में अनुबंध आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 10 पद सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती कोटे से बाल विकास परियोजना अधिकारी के 4 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यकारी अभियंता (सिविल) में प्रतिनियुक्ति पर आरक्षित 2 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला ऊना के राजकीय डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक में कॉमर्स में सहायक प्रोफेसर के दो पद, अधीक्षक ग्रेड-2 का एक पद तथा वरिष्ठ सहायक का एक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने वन विभाग के वन्यप्राणी विंग में नियुक्ति के लिए पशु पालन विभाग के कैडर को समाहित करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी के नौ पद तथा वैटनरी फार्मासिस्ट के नौ पद सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की।

बैठक में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसील कल्याण अधिकारी के चार रिक्त पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रसार अधिकारी (उद्योग) के दो रिक्त पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में नगर नियोजन विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर का एक पद तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायक के पांच पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हिप्पा में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुटंककों के दो पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में डॉ.वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) में सहायक वैज्ञानिक/समानांतर (ऐन्टोमोलॉजी) के दो पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल पपरोला के रोग-निदान, स्वस्थीवृता तथा पंचकर्मा सहित तीनों विभागों में रीडर के एक-एक पद को प्रोफैसर के पद पर स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में नागरिक अस्पताल बैजनाथ को 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीड़ को आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कफोटा को आवश्यक पदों के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत ग्वालपुर के तुमान में दो पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल द्वारा किन्नौर जिला के शौंग में स्वास्थ्य उप-केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा तीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

सिरमौर जिला के टिम्बी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्राम पंचायत अरजौली के जासवी में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री के नूरपुर दौरे के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर की ग्राम पंचायत नागणी के रिन्ना में स्वास्थ्य उप-केन्द्र को तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की धामी उप-तहसील के पाहल में तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिला के घानवी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्टाफ के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।

बैठक में कुल्लू जिला के दलाश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को आवश्यक स्टाफ सहित तीस बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा स्वास्थ्य उप-केन्द्र चोवाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल की बैठक में शिमला जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरस्वतीनगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जुब्बल तहसील के झड़ग में आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में चम्बा जिला में तीन पदां के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र चुहान (गढ़) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में इंदिरा गांधी मैडिकल कालेज शिमला में रेडिएशन सुरक्षा अधिकारी (रेडियोलॉजी) के एक पद को सहायक निदेशक (रेडिएशन सेफटी) में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कुनिहार में उप-तहसील कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमण्डल द्वारा मौजूदा 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सोलन जिला के धर्मपुर के अलावा) को स्टेट ऑफ दी आर्ट आई.टी.आई. बनाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल द्वारा कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में स्नातक स्तर पर भू-विज्ञान विषय आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल द्वारा शिमला जिला के कोटखाई तथा सिरमौर जिला के शिलाई में मापदण्डों के अनुरूप नए अग्नि शमन चौकियां खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल द्वारा सिरमौर जिला के नाहन, ऊना तथा बिलासपुर में महिला पुलिस थाने खोलने का निर्णय लिया गया।

बैठक में शिमला जिला के रामपुर के कुहल तथा सिरमौर जिला के रेणुकाजी विधानसभा की ग्राम पंचायत नेहरस्वार के कैंथघाट में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल द्वारा शिमला जिला के क्वार में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया उपमंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल द्वारा ऊना जिला के लठियाणी में आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित नियमित वैटनरी औषधालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में शिमला रेलवे पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत परवाणू के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई, बशर्ते हिमाचल प्रदेश रेलवे पुलिस मौजूदा श्रमशक्ति में से आवश्यक स्टाफ की आपूर्ति युक्तिकरण के माध्यम से सुनिश्चित बना सके।

मंत्रिमण्डल द्वारा मण्डी जिला के नगर परिषद से 14 राजस्व मुहाल को नेरचौक नियोजन क्षेत्र बनाने तथा मौजूदा नेरचौक विशेष क्षेत्र के पांच मुहालों से गुटकर विशेष क्षेत्र सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल द्वारा कुल्लू घाटी नियोजन क्षेत्र के कुल्लू-भुन्तर समूह के लिए विकास योजना के प्रारूप तथा रामपुर नियोजन क्षेत्र के लिए संशोधित विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल द्वारा कुल्लू जिला की मलाणा ग्राम पंचायत तथा कांगड़ा जिला की मुनगल तथा मण्डी जिला की वाही-सरही के क्षेत्र को पुलिस चौकी पतलीकुहल, चढ़ीधार तथा निहरी को क्रमशः पुलिस चौकी धुन्खरा, पुलिस चौकी लम्बागांव तथा पुलिस चौकी पांगणा के अधीन हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल द्वारा मण्डी जिला के नेरचौक स्थित लालबहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सिविल तथा इलैक्ट्रिकल उपमण्डल खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER SHIMLA
DIVISION NO.III, HPPWD SHIMLA-3
www.hppwd.gov-in E mail: ee-sm13-hp@nic.in Phone/Fax No.:- 0177-2652832.

NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form No. 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Shimla Division HPPWD Shimla-3ed and eligible contractors enlisted in H.P.P.WD so as to reach in the office on or before 22-07-2017 upto 10:30 A.M. And will be opened on the same day at 11:00 A.M. in the presence of the intending contractors/firms or their authorized representatives.The tender form can be had from his office against cash payment (Non refundable) on any working day up to 4:00 PM dated 21.07.2017 and the application for issueof tender form shall be received up to 4.00 P.M. on 20-07-2017.

The Earnest Money in the shape of National Saving Certificat/Time deposit Account/saving account in any of the post office in HP duly pledged in favour of the Executive Engineer, Shimla Division No.III, must accompany with application form for the tender offer. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The Executive Engineer reserves the right to reject offer of the tender without assigning any reason there to. Other conditions are applicable as perform No. 6&8. The offer shall remain open for 90 days.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time	Form No.	Cost of Form
1.	S/R to Jawahar Lal Nehru Govt. Degree College of the Arts. Chaura maidan Shimla.(SH:- C/O Temporary sheds in the premises of jawahar Lal Nehru Degree College of fine Arts. Chaura Maidan Shimla	Rs.6,77,433/-	Rs.13,550/-	Two Month	6&8	350/-

Terms and Conditions:-
1. The contractor/firm shall have his sale Tax No. and attested copy of the same be atteched with the application for issue of tender form.
2. The contractor/firm should attach attested copy of registration/renewal.
3. Copy of PAN card be attached with the application form.

Adv. No.- 1241/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शिमला अब स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल

शिमला/शैल। भारत सरकार के केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 28 अन्य शहरों के साथ शिमला को 'स्मार्ट सिटी' की सूची में शामिल किया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में शहरी परिवर्तन पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 'स्मार्ट सिटी मिशन' की तीसरी व अंतिम सूची में की गई।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला के नागरिकों को राजधानी को स्मार्ट सिटी में शामिल होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह खुशी का क्षण है और स्मार्ट सिटी का टैग शिमला के लोगों के बेहतर मानकीकरण और विकास में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बारे 31 मार्च, 2017 को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। स्मार्ट सिटी परियोजना से शहर में जलापूर्ति, मल निकासी, जल निकासी व्यवस्था, शहरी परिवहन, ई. गवर्नेंस, निर्माण क्षमता तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसी बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने में मदद मिलेगी।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन व पार्किंग प्रावधानों के अलावा पैदल यात्रियों के लिये सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बरसाती पानी तथा जल-स्त्रोतों, वन क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण टैंक, क्षेत्रीय अस्पताल के पुनरूद्धार, आग व अन्य खतरों को कम करने के उपायों का प्रबंधन अब कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्ताव में इन सभी बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि इको-टूरिज्म, साहसिक खेल गतिविधियों, परिवहन के वैकल्पिक साधनों को विकसित करने को अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी वर्तमान में झुग्गियों में रहने वाले लगभग 800 परिवारों को कानूनी पुनर्वास उपलब्ध करवाएगी।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि शिमला के लिये 2906 करोड़ रुपये का स्मार्ट सिटी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस राशि में लोअर बाजार, सब्जी मण्डी, गंज और कृष्णानगर के पुनः विकास के लिये 1252 करोड़ रुपये, सर्कुलर रोड की रेट्रो फिटिंग व शहर के तीन ट्रांजिट कॉरीडोर के लिये 1280 करोड़ रूपये, शहर में यातायात प्रबंधन तथा नागरिक सुरक्षा योजना के लिये 197 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, शिमला शहर के लोगों की सुविधा के लिये ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, भवन सुरक्षा, आपदा निवारण तथा खुले व मनोरंजक स्थलों के विकास को भी तवज्जो प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि शिमला के नागरिकों के 57 प्रतिशत सुझावों को शामिल करने के अलावा प्रस्ताव पर वार्ड बैठकों में भी विचार विमर्श किया गया, जिसे नगर निगम शिमला ने मंजूरी दी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इसके अलावा वह शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल करने के लिये केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू से अनेक बार मिल चुके हैं। उन्होंने शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल करने के लिये केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।

कैंसर इलाज के लिए अधिकतम 2.25 लाख रुपये की सीमा तय

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना तथा हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी

स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजनाओं के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी निजी अस्पताल सघन देखभाल के तहत कैशलैस चिकित्सा उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 1.75 लाख रुपये सालाना तथा परिवार के आधार पर कैंसर इलाज के लिए अधिकतम 2.25 लाख रुपये की सीमा तय की गई है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना इस योजना के लिए राज्य नोडल एजेंसी होगी। सघन देखभाल के अन्तर्गत मनोनयन के लिए इच्छुक अस्पतालों में हृदय चिकित्सा, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जेनिटो यूरिनरी सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, रेडियेशन ऑनकॉलोजी, ट्रामा, ट्रांसप्लांट सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, सर्जिकल गेस्ट्रो एंटेरोलॉजी, हेमोफीलिया तथा कैंसर की चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अस्पताल हिमाचल प्रदेश योजना सोसायटी के साथ अनुबंध करेंगे तथा उन्हें केवल पूर्व निर्धारित पैकेज दरों पर सघन देखभाल सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। अस्पतालों को स्मार्ट कार्ड धारक परिवारों को कैशलैस चिकित्सा उपलब्ध करवानी होगी तथा चिकित्सा की राशि राज्य नोडल एजेंसी द्वारा पूर्व निर्धारित पैकेज दरों के अनुसार दावा पत्र व सम्बन्धित दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरांत अदा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना तथा हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सहायक एजेंसी इन अस्पतालों की नियमित चिकित्सा लेखा परीक्षा करेगी। इस उद्देश्य के लिए राज्य नोडल एजेंसी एक एजेंसी का चयन करेगी, जो सघन देखभाल के अन्तर्गत दावों की नियमित लेखा परीक्षा करवाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अस्पताल इस योजना के दुरूपयोग /जालसाजी/शोषण/अनावश्यक प्रक्रिया में संलिप्त पाया गया तो तत्काल प्रभाव से उस अस्पताल को मनोनीत सूची से हटा दिया जाएगा व उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू की जाएगी।

किसानों की आय को दोगुणा करना नीति आयोग का मुख्य लक्ष्य

शिमला/शैल। भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने आयोजित बैठक में कहा कि नीति आयोग का मुख्य लक्ष्य आगामी पांच वर्षो में किसानों की आय को दोगुना करना है और हिमाचल प्रदेश को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रूप-रेखा तैयार करने की आवश्यकता है। बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्य व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने नीति आयोग के गठन के उपरांत हिमाचल के लम्बित मामलों व विभिन्न समस्याओं के निवारण बारे विस्तृत परिचर्चा की और सुझाव दिए।

प्रो. रमेश चंद ने कहा कि नीति आयोग के गठन के उपरांत आयोग की भूमिका निधि आवंटन से नीति निर्माता तथा थिंक टैंक के रूप में परिवर्तित हुई है। इसके अतिरिक्त, नीति निर्माता के तौर पर आयोग रणनीतिक मुद्दों पर भी सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि संसाधनों से आशातीत वृद्धि संभव है और राज्यों के स्तर पर योजना के विकेन्द्रीकरण से आयोग को मजबूत करने तथा इन योजनाओं को ग्राम स्तर तक ले जाने में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय सहायता में कटौती पर चिंता जाहिर करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि योजना आयोग के दौरान राज्य को 90:10 के अनुपात से केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती थी और नीति आयोग के गठन के उपरांत इसमें कमी कर दी गई। हालांकि, अब इसे पुनः बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के गठन के उपरांत राज्य को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में कम निधि मिलने तथा औद्योगिक पैकेज के बंद होने से गहरा झटका लगा। उन्होंने कहा कि राज्य ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति के लिये भारत सरकार को भेजा है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने नीति आयोग से वन संरक्षण में अहम् भूमिका निभाने तथा पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए हिमाचल को बोनस प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने 250 से कम की जनसंख्या वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लाने की अपील की ताकि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत छोटी बस्तियों तक भी सड़क सुविधा प्रदान की जा सके।

कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने देश-भर में किसानों की दयनीय हालत पर चिंता जाहिर करते हुए किसानों के लिए आय सहायता व्यवस्था आरंभ करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो किसानों की हालत दिनों-दिन खराब होती जाएगी और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत धनराशि 90 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है तथा प्रधानमंत्री कृषि योजना व सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत भी अपर्याप्त धन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने ट्राउट मछली पालन को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाने की अपील की।

इससे पूर्व, मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने कहा कि राज्य सरकार अधिकांश लक्ष्यों को वर्ष 2022 तक प्राप्त करने की स्थिति में है। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2016-17 और 2017-18 के बजट भाषणों में इसकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। हालांकि, सभी स्तरों पर और अंतिम छोर तक समावेशी विकास सुनिश्चित बनान एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रदेश सरकार ने सभी की सहभागिता से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रणनीति, परिकल्पना व कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया पहले ही आरम्भ कर दी है।

फारका ने राज्य की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा वित पोषण में की गई कमी से आगामी पांच वर्षो में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में आड़े आएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 105 करोड़ रुपये और बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 125 करोड़ रुपये के प्रतिपूर्ति दावे लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में राज्य को प्राप्त राशि के मुकावले 148 करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए हैं।

भारत सरकार की नीति आयोग के सलाहकार अनिल श्रीवास्तव ने अपनी प्रस्तुति में सहकारी संघवाद पर बल देते हुए कहा कि इसके अंतर्गत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति निर्माण में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय दीर्घकालीन परिकल्पना, सात वर्षीय मध्य अवधि की रणनीति और तीन वर्षीय लघु अवधि कार्य -योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने नीति के प्रमुख सूचकांकों पर विस्तृत जानकारी दी।

इससे पूर्व, अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यवाही का संचालन भी किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों के प्रमुख अभियन्ताओं ने भी इस अवसर पर आयोग के समक्ष संबंधित विभागों की समस्याएं रखीं व सुझाव दिए।

देश मे व्यापार करने के तरीके को बदल देगा जीएसटी: विशेषज्ञ

शिमला/शैल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू करना देश में व्यापार करने के तरीके को बदल देगा। उद्योग सदस्यों को जीएसटी अपनाने में मदद करने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल ने जीएसटी'गेयरिंग अप फॉर चेंज विषय पर काला अम्ब में कार्यशाला

आयोजित की। इस कार्यशाला में उद्योगों से 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेंट्रल एक्साईज एंड सर्विस टैक्स शिमला के डिप्टी कमिश्नर विवेक गुप्ता ने कहा कि उद्यमियों को जीएसटी के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इसे आसान बना रही है और जीएसटी के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी सीबीईसी की वेबसाईट पर पाई जा सकती है। सुविधा केंद्रों को भी जानकारी मुहैया करवाने के लिए तैयार किया गया है।

सरदूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी में सीनियर एसोसिएट अंकिता भसीन ने कहा कि जीएसटी वर्तमान में मौजूद मल्टी लेवल टैक्स सिस्टम का स्थान लेने को तैयार है और इसके आने के बाद केवल एक टैक्स होगा। ऐसी उम्मीद है कि जीएसटी आने के बाद एक सकारात्मक माहौल तैयार होगा जिससे व्यापार करना आसान होगा हालांकि अभी उद्योगों को इस टैक्स से फैंडली होने में कुछ समय जरूर लगेगा।

नरेश के सिंगला एंड एसोसिएट्स के पार्टनर तथा आईसीएआई में जीएसटी एक्सपर्ट अर्चित सिंगला ने कहा कि जीएसटी आने के बाद हम ज्यादा प्रभावी, बाधा रहित व्यापार और उद्यमों के कार्य देखेंगे। जीएसटी प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा साथ ही इससे मल्टी लेयर टैक्स का विपरीत प्रभाव भी ग्राहकों को नहीं झेलना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन राजेश साबो ने कहा कि जीएसटी मल्टी लेयर इनडायरेक्ट टैक्स के प्रभावों को समाप्त करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय व राज्य के टैक्स व डयूटी को समाहित कर लेगा। उन्होंने कहा कि सीआईआई उद्योगों को जीएसटी से रूबरू करने और इसके प्रभावों को समझाने के लिए गंभीरता से काम कर रहा है और अभी तक 100 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित कर चुका है। सीआईआई एक हेल्प डेस्क gsthelpdesk-nr /cii-in को भी स्थापित किया है जिसपर उद्योग सदस्य जीएसटी से जुड़ी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं।

खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है

स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

दलित राजनीति के आईने में राष्ट्रपति का चयन

देश के राष्ट्रपति के लिये सत्तारूढ़ एनडीए ने बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद को तो विपक्ष ने बिहार की ही बेटी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों ही उम्मीदवार दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन रामनाथ कोविंद के नाम पर जिस अन्दाज में केन्द्र सरकार के ही वरिष्ठ मन्त्री और लोजपा के शीर्ष नेता रामविलास पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है उससे यह चयन दलित राजनीति का केन्द्र बनकर रह गया है। क्योंकि पासवान ने एन डी ए द्वारा रामनाथ कोविंद का नाम पेश किये जाने को उन लोगों के गाल पर तमाचा करार दिया जो भाजपा को दलित विरोधी मानते हैं। पासवान की इसी प्रतिक्रिया का परिणाम है कि विपक्ष ने भी दलित वर्ग से ही कोविंद से भी बड़ा चेहरा उतारने का फैसला लिया और मीरा कुमार के रूप में यह नाम सामने आया है। लेकिन जिस तरह से यह बहस बढ़ाई गयी है उससे यह लगने लगा है कि शायद यह पद इस बार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है और यही इस बहस का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है जहां इस सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद को भी दलित राजनीति के मानक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

लेकिन इसी बहस से एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या पासवान ने इस बहस को एक मकसद के साथ तो नहीं मोड़ा है इस ओर? क्योंकि पिछले एक लम्बे अरसे से देश के विभिन्न राज्यों से आरक्षण को लेकर आन्दोलन उठे हैं। हार्दिक पटेल से लेकर जाट आन्दोलन तक देश ने देखे हैं। इन आन्दोलनो में या तो इन वर्गो के लिये भी आरक्षण की मांग की गई या फिर सारे आरक्षण को सिरे से समाप्त करने की मांग उठाई गयी है। इस समय अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आजादी के बाद 1957 में काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब सरकार ने पहली बार अनुसूचित जातियों की सूची प्रकाशित की थी उसमें ऐसी 1100 जातियों का उल्लेख है। इसके बाद 1980 में आयी मण्डल आयोग की रिपोर्ट में 3743 अन्य पिछड़ी जातियों का उल्लेख है जिसके लिये आरक्षण की सिफारिश की गयी थी। अनुसूचित जातियों के लिये पहली बार अंग्रेज शासन के दौरान जब राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानन्द तथा गांधी जैसे समाज सुधारकों के विचारों से प्रभावित होकर समाज सुधार और दलितोंद्धार राष्ट्रीय आन्दोलन के अंग बन गये। अंग्रेजों ने इस स्थिति को भांपते हुए पूना पैकट के तहत आरक्षण का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अनुसूचित जातियों के लिये प्रांतों की विधान सभाओं के अन्दर 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया। 1935 से शुरू हुआ यह राजनीतिक आरक्षण आज तक चल रहा है। यह राजनीतिक आरक्षण अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये है लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के लिये नही है। काका कालेलकर और फिर मण्डल आयोग की रिपोर्टो के परिणामस्वरूप इनके लिये सरकारी नौकरियों और शिक्षा के लिये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया।

संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 38, 46, 164, 275, 330, 332, 334, 335, 338, 340, 341, 342 और 366 में सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता के साथ-साथ पिछड़े वर्गो के लिये राज्यों की सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और व्यवस्थापिकाओं में स्थान आरक्षित करने की भी अनुमति दी गयी है। अनुच्छेद 16(4) के मूल प्रारूप में नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिये आरक्षण की बात रखी गयी थी। परन्तु डा. अम्बेडकर ने इसके साथ पिछड़ा शब्द जुड़वा दिया ताकि आरक्षण की शर्त और दशा स्पष्ट हो सके। लेकिन मण्डल आयोग की सिफारिशों पर अमल 1989 में वी.पी. सिंह सरकार के समय हुआ। इस अमल का विरोध इतने बड़े स्तर पर हुआ कि यह आन्दोलन हिंसक तक हो गया। कई राज्यों में आन्दोलनकारियों ने आत्मदाह तक किये। इसी आरक्षण विरोधी आन्दोलन के परिणामस्वरूप वी.पी.सिंह की सरकार गयी और सरकार जाने के साथ ही आन्दोलन भी समाप्त हो गया। इस आरक्षण विरोधी आन्दोलन को आर. एस.एस. का संरक्षण और समर्थन प्राप्त था यह जगजाहिर है। इस आन्दोलन के बाद आज तक आरक्षण का विरोध उस तर्ज पर सामने नहीं आया है जबकि आरक्षण की व्यवहारिक स्थिति वैसी ही बनी हुई है। इस समय केन्द्र में भाजपा को अपने दम पर प्रचण्ड बहुमत हासिल है। इस दौरान जहां आरक्षण को लेकर कुछ आन्दोलन सामने आये हैं वहीं पर संघ नेतृत्व की ओर से भी कई ब्यान आ चुके हैं। आरक्षण प्राप्त वर्गो से ''क्रिमी लेयर'' को बाहर करने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय बहुत पहले दे चुका है परन्तु इस फैसले पर सही अर्थो में अमल नहीं हो पाया है क्योंकि इस लेयर का दायरा हर बार बढ़ा दिया जाता है। आज तक आरक्षण से सम्पन्न हो चुके किसी भी परिवार की ओर से यह सामने नहीं आया है कि उसने अपने को आरक्षण से बाहर कर दिये जाने का आग्रह किया हो। पासवान, मीरा कुमार या कोविंद कोई भी हो सबको चुनाव आरक्षित सीट से ही लड़ना है। राष्ट्रपति को संविधान में इन वर्गो के लिये विशेष अधिकारी का अधिकार भी प्राप्त है और इसी अधिकार के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुए हैं।

इस समय आरक्षण को लेकर जो स्थिति परोक्ष/अपरोक्ष में उभर रही है वह एक बार फिर 1991-1992 जैसे स्वरूप में कब सामने आ जाये इसकी संभावना बराबर बनी हुई है। आज इस संभावित परिदृश्य में राष्ट्रपति की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी यह तय है। ऐसे में आज बहस का रूख इस आकर्षित करने की दिशा में यह प्रयास पाठकों के सामने है।

हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन ने छुई नई ऊंचाईयां

प्रदेश में संयुक्त साहसिक पर्यटन अभियान सफलतापूर्वक आयोजित

हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यटन एवं नागरिक उडयन विभाग, पर्यटन विकास निगम द्वारा भारतीय वायु सेना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संयुक्त साहसिक पर्यटन अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

12 से 17 जून, 2017 तक आयोजित यह अभियान कई प्रकार की साहसिक गतिविधियों का गवाह बना, जिसमें भारी संख्या में पर्यटकों व स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। भारतीय वायु सेना के तत्वाधान में साहसिक गतिविधियां जैसे रिवर-राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, रैपलिंग व रिवर-क्रोसिंग आदि आयोजित की गई। पर्यटन विकास निगम द्वारा अब आने वाले समय में साहसिक गतिविधि प्रिय लोगों के लिए अधिक पैकेजिज आधारित गतिविधियों की योजना बनाई जा रही है तथा प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा भविष्य में राज्य में अतिरिक्त साहसिक गतिविधियों की संभावनाओं के दोहन के लिए इस तरह के अधिक से अधिक अभियान आयोजित करने की कार्य-योजना बनाई जा रही है।

कुपर पीक, खड़ापत्थर, सिरमौर जिले की चूड़-चांदनी पीक और शिमला के शाली देवी पीक तक ट्रैकिंग रूट आरम्भ किए गए हैं। इसी प्रकार से लाहौल के सरचू, किन्नौर के सांगला और कल्पा और स्पिति के काजा में कैंपिंग अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ-साथ यूथ ऐसोशियसन ऑफ इण्डिया द्वारा डलहौजी, कुल्लू और मनाली में जबकि सांगला वैली के बासपा, किन्नौर के कल्पा, स्पिति के ताबो, अलहिलाल (तारागढ़), कांगड़ा के धर्मशाला, कुल्लू के समीप शोजा, शिमला के समीप मशोबरा और बल्देयां

आयोजित यह अभियान अपनी किस्म का पहला अभियान है जिसके तहत हिमाचल में साहसिक अवसरों को प्रदर्शित कर युवा पीढ़ी को भारतीय वायु सेना की सेवाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस अभियान को सफल बनाने व इसका हिस्सा बनने के लिए विद्यार्थियों, पुलिस व आईटीबीपी के जवानों, स्थानीय साईकलिंग ऐसोशियसन, होटल व रैस्टोरेंट ऐसोशियसन, राष्ट्रीय व स्थानीय मीडिया, ट्रैवल लेखकों और स्थानीय गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था।

अभियान के तहत आयोजित विभिन्न गतिविधियों में स्काईडाईविंग व पैरासेलिंग शिमला के जुब्बड़-हट्टी हवाई अड्डे में आयोजित की गई जबकि शिमला से त्ततापानी तक आयोजित माऊंटेन टैरन बाईक प्रतियोगिता में काफी संख्या में पर्यटकों व स्थानीय लोगों ने भाग लिया। स्थानीय साईकलिंग ऐसोशियसन और दूसरे साईकलिस्टों ने भारतीय वायु सेना के डेयर डेविल ग्रुप के साथ मशोबरा तक इस अभियान में भाग लिया। अभियान के अंतर्गत पैरा-ग्लाईडिंग कांगड़ा के बीड़-बिलिंग में जबकि ट्रैकिंग व कैंपिंग मनाली से ब्यास-कुंड तक आयोजित की गई जोकि 17 जून को रिवर-राफ्टिंग के साथ कुल्लू में सम्पन्न हुई।

प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा हाल ही में भारतीय नेवी अधिकारियों के लिए एक साहसिक यात्रा का आयोजन किया गया जिसके तहत बोर्डिंग-लोजिंग व यात्रा सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ कई प्रकार की

पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में विभिन्न प्रकार की साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बोर्डिंग-लॉजिंग व यात्रा सुविधा के साथ कई साहसिक पर्यटन पैकेजिज भी शुरु किए गए हैं। निगम पर्यटकों की जरुरत व शौक के अनुसार साहसिक गतिविधियां चलने के लिए शीघ्र ही प्रदेश की विभिन्न एजैंसियों से संपर्क साधने जा रहा है।

निगम द्वारा भारतीय नेवी व वायु सेना बलों के लिए कई साहसिक पर्यटन पैकेजिज सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। इन पैकेजिज् के तहत अच्छा भोजन, रिहायश और बस यात्रा जैसी सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ निगम द्वारा ट्रैकिंग, कैंपिंग, रिवर-राफ्टिंग, रैपलिंग, रिवर-क्रोसिंग पैरा-ग्लाईडिंग और माऊंटेन बाईकिंग आदि कई गतिविधियां सेना बलों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित की हैं। निगम द्वारा साहसिक प्रवास पैकेजिज् के लिए प्रशिक्षित गाईड उपलब्ध करवाए गए हैं। निगम द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में साहसिक गतिविधियां चलाने के लिए शीघ्र ही प्रमाणित ऐजैंसियों से संपर्क साधा जाएगा जिससे बोर्डिंग-लॉजिंग व यात्रा सुविधा के साथ कम कीमत पर आकर्षक पैकेजिज् उपलब्ध करवाए जा सकेंगे।

प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में साहसिक खेल अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। बड़ा से भंगाल ट्रैक, पिन-पार्वती तक ट्रैकिंग रूट, तथा किन्नौर से कैलाश, स्पिति से गढ़वाल, भरमौर से पदुम, हाटु-पीक, नारकण्डा, में निजि क्षेत्रों में कैंप चलाए जा रहे हैं।

इसके साथ ही दियो-टिब्बा, रोहतांग -पास, चन्द्रखनी-पास, हनुमान टिब्बा और चन्द्राखानी पास में हैली-स्किंईग उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी प्रकार से मांऊटेन-बाईकिंग और मोटर बाईकिंग रुट की सुविधा लेह-मनाली, मनाली-दमफुग, ताबो-काजा, काजा-लोसर, शिमला-रामपुर और रामपुर-सांगला उच्चमार्गो में उपलब्ध करवाई जा रही है। मांऊटेन मोटर-साईकलिंग को मनाली-लेह और लाहौल-स्पिति सड़कों पर, पर्वतारोहण और रॉक-क्लाइविंग को मनाली में प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग मनाली, शीतीधार पीक, ब्यास-कुंड क्षेत्र, चन्द्राभाग रेंज, पीरपंजाल, धौलाधार रेंज, फुटहिल ऑफ हनुमान टिब्बा, दियो-टिब्बा गिरिगंगा और चांशल में रैपलिंग के अवसर उपलब्ध करवा रहा है।

पैरा-ग्लाईडिंग की विश्व स्तरीय सुविधा कांगड़ा घाटी के बीड़, कुल्लू जिला के बिजली-महादेव, मनाली और सोलंग घाटी और स्किंईग की सोलंग घाटी और नारकण्डा में विकसित की गई है। कुपर और खड़ापत्थर में इस सुविधा को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। जीप-सफारी, जोरबींग और एंगलिंग के अवसर पर्यटकों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रिवर-राफटिंग और जल-क्रिड़ा गतिविधियां प्रदेश में अन्य आकर्षण हैं जोकि पर्यटकों को प्रदेश में मौजूद विभिन्न नदियों में उपलब्ध करवाए जा रहें हैं।

अंतरिक्ष की लंबी यात्रा

बैलगाड़ी पर रॉकेट ले जाने से लेकर मंगल तक

*के.वी वेंकट सुब्रमण्यन

उच्च-तकनीक वाले सबसे वजनी भू-स्थैतिक संचार उपग्रह, जी-सैट-19 को 05 जून को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़े जाने के बाद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस उपग्रह को सबसे शक्तिशाली देसी रॉकेट जीएसएलवी मार्क- III द्वारा छोड़ा गया।

जीएसएलवी मार्क- III 18 दिसंबर, 2014 को पहली प्रायोगिक उड़ान के साथ एक प्रोटोटाइप क्रू कैप्सूल ले गया था। उपकक्षीय मिशन ने वैज्ञानिकों की यह समझने में मदद की कि यह यान वायुमंडल में कैसे काम करता है। साथ ही कैप्सूल का परीक्षण भी किया गया।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए इस वर्ष यह तीसरी उपलब्धि थी। इसने खुद के किफायती लेकिन प्रभावी क्रायोजनिक इंजन और अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर पर कक्षा में 4 हजार किलोग्राम तक के भारी भरकम भू-स्थैतिक उपग्रहों को विकसित करने की देश की चाहत को पूरा किया।

इससे पहले 05 मई को भारत ने संचार सुविधा को बढ़ाने और पहला दक्षिण-एशिया उपग्रह (एसएएस) छोड़कर अपने 6 पड़ोसियों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को अनमोल तोहफा दिया था। 2,230 किलोग्राम के संचार अंतरिक्ष यान ने क्षेत्र में नए द्वार खोल दिए और भारत को अंतरिक्ष कूटनीति में अपने लिए अनोखा स्थान बनाने में मदद की।

इसरो द्वारा निर्मित और भारत द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित, भू-स्थैतिक संचार उपग्रह-9 (जीसैट-9) अपने साथ जीएसएलवी-एफ09 रॉकेट ले गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे अभूतपूर्व विकास बताते हुए एक संदेश में कहा कि जब क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है तो आकाश भी कोई सीमा नहीं है।

पृथ्वी की कक्षा में कार्टोसेट-2 श्रृंखला के उपग्रह सहित रिकॉर्ड-104 उपग्रहों के लिए पोलर सैटलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी सी-37) का इस्तेमाल करने के बाद फरवरी में अंतरिक्ष एजेंसी दुनियाभर में सुर्खियों में आ गयी थी। इस मास्टर स्ट्रोक ने भारत को छोटे उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवा प्रदात्ता के रूप में स्थापित कर दिया।

इन उपलब्धियों ने अंतरिक्ष की दौड़ में इसरो के लिए एक विशिष्ट स्थान बना दिया। प्रधानमंत्री के अंतरिक्ष प्रेम और इसरो से उनका जुड़ाव अंतरिक्ष विभाग के लिए इस वर्ष के बजट में भी दिखाई दिया जिसमें भारी 23 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी। वर्षों से चल रहा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय अनिवार्यता, और लोगों की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए चल रहा है। भारत अपने उपग्रहों का इस्तेमाल विशेष रूप से विकास संबंधी उद्देश्यों नागरिक (पृथ्वी की निगरानी, रिमोट सेंसिंग, संचार, मौसम विज्ञान) और रक्षा उद्देश्यों के लिए करता है। इसमें पर्यावरण अवकर्षण, भूमि का कटाव, मछली पकड़ने के संसाधनों पर निगरानी, बाढ़ और सूखे पर निगरानी, खनन, खनिज विज्ञान संबंधी संसाधनों का सर्वेक्षण और वन्य जन्तु पार्कों के लिए भूमि की कवरेज का पता लगाना शामिल है। अंतरिक्ष आधारित एप्लीकेशनों जैसे टेली-शिक्षा और टेली-मेडिसन ने इन आधारभूत जरूरतों तक ग्रामीण आबादी की पहुंच बढ़ा दी है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत अपने अंतरिक्ष मिशन में तेजी लाया है। 2016 की करीब दर्जनभर उपलब्धियों में दिसम्बर में रिमोर्ट सेंसिंग उपग्रह रिसोर्ससैट-2 के सफलतापूर्वक कार्य करने और जून में अकेले अंतरिक्ष उपग्रह में 20 उपग्रहों, 3 नेवीगेशन उपग्रहों और जीसैट-18 संचार उपग्रहों का रिकॉर्ड प्रक्षेपण शामिल है।

2015 में इसरो ने नवंबर में जीसैट-15 संचार उपग्रह और सितम्बर में मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जरवेटर एस्ट्रोसेट छोड़ा। स्वदेश में विकसित उच्च प्रक्षेपक क्रायोजनिक रॉकेट इंजन का 800 सेकेंड के लिए जमीनी परीक्षण किया गया। इसके अलावा पीएसएलवी द्वारा जुलाई में पांच उपग्रह और मार्च में भारतीय क्षेत्रीय नेवीगेशन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) में चौथा उपग्रह आईआरएनएसएस-1डी छोड़ा गया।

2014 में संचार उपग्रह जीसैट-16 दिसंबर में छोड़ा गया और कक्षा में स्थापित किया गया। आने वाले वर्षों में इसरो के वैज्ञानिकों ने उपग्रह प्रक्षेपण की श्रृंखला तैयार कर रखी है। अगली प्रमुख परियोजना भारत का चंद्रमा पर दूसरा अन्वेषण मिशन, चंद्रयान-2 भेजना है। इसके चंद्रमा की धरती का खनिज विज्ञान संबंधी और तात्विक अध्ययन करने की उम्मीद है। इसे 2018 की पहली तिमाही में छोड़ने की तैयारी है। 10 वर्ष पूर्व चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक छोड़ा गया था।

इसरो की अगली बड़ी योजना सौर प्रभामंडल (कोरोनाग्राफ के साथ एक टेलीस्कोप), फोटोस्फेयर, वर्णमण्डल (सूर्य की तीन प्रमुख बाहरी परतें) और सौर वायु का अध्ययन करने के लिए सूर्य में वैज्ञानिक मिशन भेजना है। श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी-एक्सएल द्वारा इसे 2020 में छोड़ा जाना है। आदित्य-एल1 उपग्रह कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा जो पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है।

आदित्य-एल1 मिशन इस बात की जांच करेगा कि क्यों सौर चमक और सौर वायु पृथ्वी पर संचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स में बाधा पहुंचाती है। इसरो की उपग्रह से प्राप्त उन आंकड़ों का इस्तेमाल करने की योजना है ताकि वह गर्म हवा और चमक से होने वाले नुकसान से अपने उपग्रहों का बेहतर तरीके से बचाव कर सके।

जल्द ही भारत पहली बार शुक्र ग्रह का भी उपयोग करेगा और संभवत: 2021-2022 के दौरान दूसरे मंगल ओर्बिटर मिशन के साथ लाल ग्रह पर लौटेगा। उसकी मंगल की धरती पर रोबोट रखने की योजना है।

भारत की अंतरिक्ष यात्रा 53 वर्षों का सफर पूरा कर चुकी है। देश ने पहली बार 21 नवंबर 1963 को केरल में मछली पकड़ने वाले क्षेत्र थुंबा से अमेरिकी निर्मित दो-चरण वाला साउंडिंग रॉकेट (पहला रॉकेट) 'नाइक-अपाचे' का प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष पर पहला हस्ताक्षर किया।

चूंकि तिरुअनंतपुरम के बाहरी हिस्से स्थित थुंबा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन पर कोई इमारत नहीं थी इसलिए बिशप के घर को निदेशक का कार्यालय बनाया गया, प्राचीन सेंट मैरी मेगडलीन चर्च की इमारत कंट्रोल रूम बनी और नंगी आंखों से धुआँ देखा गया। यहाँ तक की रॉकेट के कलपुर्जो और अंतरिक्ष उपकरणों को प्रक्षेपण स्थल पर बैलगाड़ी और साइकिल से ले जाया गया था।

इसके करीब 12 वर्ष बाद भारत ने अपने पहले प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट के साथ अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया जिसे 1975 में रूसी रॉकेट पर रवाना किया गया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ.यू.आर.राव ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन दिनों बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं था। जो कुछ उपलब्ध था हमने उसका इस्तेमाल किया। यहाँ तक की हमने बैंगलोर में एक शौचालय को डेटा प्राप्त करने के केंद्र में तब्दील कर दिया।

थुंबा से सफर शुरू करने से लेकर भारत का अंतरिक्ष सफर काफी आगे निकल चुका है। भारत ने चंद्रमा संबंधी अनुसंधान शुरू करने, उपग्रह बनाने, अन्य के लिए भी, विदेशी उपग्रहों को ले जाने और मंगल तक पहुंचने में सफलता अर्जित कर दुनियाभर में अपनी पहचान बना ली है।

शांति व आनंद के लिए राजयोग

बी.के सुशांत

आपाधापी भरे इस युग में जन-सामान्य बहुत कुछ हासिल करने की चाह में मानसिक अशांति और शारीरिक व्याधियों को आमंत्रण दे रहा है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में साझीदार होना वक्त की आवश्यकता है पर अंधाधुंधा दौड़ना शरीर और मन को देने वाली यंत्रणा है। 21 जून को विश्व अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जन-मानस में योग के प्रति जो सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो रही है वह वास्तव में एक सुखद अनुभव है। भारत भूमि में वर्षों से योग प्रचालित रहा है और आज विश्व भी इसे मान्यता प्रदान कर रहा है। राजयोग एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे शांत चित्त से कोई भी कर सकता है।

राजयोग अन्तर जगत की ओर एक यात्रा है। यह स्वयं को जानने या यूँ कहें कि पुन: पहचानने की यात्रा है। राजयोग अर्थात् अपनी भागदौड़ भरी जिन्दगी से थोड़ा समय निकालकर शान्ति से बैठकर आत्म निरीक्षण करना। इस तरह के समय निकालने से हम अपने चेतना के मर्म की ओर लौट आते हैं। इस आधुनिक दुनिया में, हम अपनी जिन्दगी से इतने दूर निकल आये हैं कि हम अपनी सच्ची मन की शान्ति और शक्ति को भूल गये हैं। फिर जब हमारी जड़े कमजोर होने लगती हैं तो हम इधर-उधर के आकर्षणों में फँसने लग जाते हैं और यही से हम तनाव महसूस करने लग जाते हैं। आहिस्ते-आहिस्ते ये तनाव हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को असन्तुलित कर हमें बीमारियों में भी जकड़ सकता है।

राजयोग एक ऐसा योग है जिसे हर कोई कर सकता हैं। इसे कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। राज योग को आँखे खोलकर किया जाता है इसलिए ये अभ्यास सरल और आसान है। योग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपनी रोजमर्रा की चिन्ताओं से परे जाते है ओर हम अपने आध्यात्मिक सशक्तिकरण का आरंभ करते है। आध्यात्मिक जागृति हमें व्यर्थ और नकारात्मक भावों से दूर कर अच्छे और सकारात्मक विचार चुनने की शक्ति देता है। हम परिस्थितियों का जवाब जल्दबाजी मे देने के बजाए सोच समझ के करेंगे। हम समरसता में जीने लगते हैं। बेहतर, खुशनुम: और मजबूत रिश्ते बना अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर पाते हैं।

राजयोग करना वास्तव मे बहुत सरल है, इसलिए इस योग को दूसरे शब्दों में 'सहज राजयोग' भी कहा जाता है। परन्तु कभी कभार शुरुआत मे इसकी थोड़ी सी जानकारी की जरूरत पड़ती है। इस अभ्यास के लिए 5 सरल कदम बताए गये हैं। अभ्यास करते करते बहुत जलद ही आपको इन 5 कदमों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी-केवल एक है विचार से आप एक शान्त स्थिति में पहुंच जायेंगे।

विश्रान्ति

विश्रान्ति अर्थात अपने तनाव और उलझनों को परे रखते हुए अपने मन और शरीर को शान्त और स्थिर करना।

एकाग्रता

विश्रांत होने के बाद वर्त्मान पे अपना ध्यान केन्द्रित करना।

मनन करना

स्वयं की आन्तरिक दुनिया और अपने मूल्यों की गहराई में जाना

अनुभूति

जब मेरी समझ और मेरे अहसासो का मेल होता हैं तो और ही गहरी और सार्थक वास्तविकता की अनुभूति होती है।

योगाभ्यास

एक ही संकल्प में एकाग्र रहके अपने मूल अस्तित्व को याद करते हुए सुस्वस्थ स्थिति को पुन: जागृत करना।

राजयोग के बारे में और जानिए ये क्या है? इसे क्यों, कैसे, कहाँ और कब किया जाये और किस प्रकार के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं।

योगाभ्यास कहाँ कर सकते है?

जीवन पहले से ही विविधताओं से भरा हुआ है, बहुत सारी गतिविधियाँ और जिम्मेदारियाँ होती हैं। ऐसे में हम राजयोग अभ्यास के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? यही तो राजयोग की सुन्दरता है कि इसे कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है।

राजयोग अभ्यास के लिए खास रूम अथवा जगह की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एकान्त और शान्त स्थान या आरामदायक कुर्सी भी चल सकती है। अपनी आन्तरिक गहराई को समझने के लिए लगातार और नियमित समय निश्चित करें। कुछ ही समय में आपको ऐसी जगह मिलेगी जिसकी तरफ आप आकर्षित होने लगेंगे जहाँ पर आपने अपनी शान्ति की स्थिति से और आत्म चिन्तन के अभ्यास से शान्ति का वातावरण बनाया होगा। ऐसी नियुक्त जगह पर आप जब ओर जितनी बार बी जाना चाहे तो जा सकते है ।

जहां भी आप कामकाज करते है, यदि आप थोड़ा सा असामान्य/रचनात्मक तरीके से सोचेंगे तो जरूर आप को अपना मैडिटेशन कहा और कैसे करना है, उस के लिए कोई अच्छा सुजाव निकलेगा।

वीरभद्र व सुक्खू की जोड़ी ने 2012 के बाद जो भी चुनाव लड़ा,वो हारा

शिमला/शैल। प्रदेश में 2012 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने जितने भी चुनाव लड़े, उसमें कांग्रेस की हार हुई हैं। ताजा हार शिमला नगर निगम में हुई । शिमला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। हालांकि यहां पिछले दस सालों से भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज कांग्रेस का परचम नहीं लहराने दे रहें हैं। बड़ी बात ये ह कि हारने के बाद न वीरभद्र सिंह ने और न ही सुक्खू ने हार की जिम्मेदारी ली।औपचारिकता के लिए ही सही कभी इस्तीफे की पेशकश भी नहीं की। दोनों अपनी कुर्सियां बचाने की जुगत में ही लगे रहे हैं। लेकिन इस जुगत में वो बाकियों को हराते जा रहे हैं, ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों में बाकी लोग क्या करेंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

इतनी बार हारने के बावजूद कांग्रेस आलाकमान जिनमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक शामिल है, की ओर से कोई कार्रवाई न करना कई सवाल खड़े कर देता है। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस आलाकमान की ओर से प्रदेश कांग्रेस का काम–काज देखने के लिए तैनात किए गए प्रभारी व सह–प्रभारी को लेकर है। मौजूदा समय में कांग्रेस की प्रभारी सोनिया दरबार में दबदबा रखने वाली अंबिका सोनी है जबकि सह प्रभारी राजा राम पाल है। राजा राम पाल कम असर के नेता हैं।

लेकिन हार पार्टी के कामकाज को लेकर आलाकमान को दी जाने वाली उनकी रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है।

2014 में सुजानपुर के उपचुनाव में मिली हार से लेकर लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटें गवां देना पार्टी के लिए कोई मामूली नुकसान नहीं था। लेकिन आलाकमान ने कोई कदम नहीं उठाया। न भ्रष्टाचार में फंसे मुख्यमंत्री को हटाया और न ही कम असर वाले पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू को लेकर कोई कदम उठाया। सुक्खू 2012 में अपना चुनाव हार गए थे।

सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस प्रभारियों की रिपोर्ट दागी रही थी। अंबिका सोनी को वैसे भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का करीबी माना जाता है। इतनी हारे इसलिए गले नहीं उतरती क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की अपनी सरकार है। लोकसभा में तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अपनी बीवी प्रतिभा सिंह मंडी लोकसभा हल्के से हार गई थी।

अभी कुछ महीना पहले हमीरपुर के भोरंज में उप–चुनाव हुआ तो पार्टी वो चुनाव भी हार गई।

सबसे बड़ी हार शिमला नगर निगम चुनाव में मिली हैं। पार्टी ने जिस तरह से ये चुनाव लड़ा उस तरह के चुनाव तो कोई कॉलेजों में भी नहीं लड़ते। वहां भी बाकायदा तैयारी की जाती है। लेकिन निगम चुनावों में न तो सरकार कहीं थी और न ही पार्टी। पार्टी के असरदार मंत्री तक चुनाव प्रचार से गायब करा दिए गए। पार्टी के असरदार विधायक चुनाव प्रचार से बाहर थे। मुख्यमंत्री खुद तीन दिन पहले चुनाव प्रचार में उतरे तो उनके साथ वो चेहरे थे जिनकी छवि जनता को अखरती है।

पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू चुनावों के लिए कोई रणनीति ही नहीं बना पाए। महिला कांग्रेस कहां थी किसी को कुछ नहीं पता। युवा कांग्रेस पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने लाडले को काबिज कराया हुआ है, युवा कांग्रेस का भी इन चुनावों में कोई नामोनिशान नहीं था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह को नेता बनाकर किसी तरह स्थापित करने में पूरा जोर लगाकर रखा हैं। कांग्रेस में उनका पूरा खेमा, नौकरशाही में उनके सारे लाडले हर समय इसी जुगत में रहते हैं कि किस तरह से वीरभद्र सिंह के लाडले को नेता बना पाएं। इसी तरह कांग्रेस के सेवादल समेत कई सारे विंग हैं, उन्होंने चुनावों में क्या किया किसी को मालूम नहीं है। अगर कुछ किया तो हारे कैसे, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है।

जबकि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से लेकर केंद्रीय प्रभारी मंगल पांडे तक को प्रचार में उतार दिया। पार्टी अध्यक्ष सतपाल सती शिमला में ही रहे। बेशक पार्टी का टॉप चेहरा धूमल प्रचार के आखिरी दिन शिमला आए लेकिन वो तब से लेकर जब तक मेयर व डिप्टी मेयर भाजपा के नहीं बन गए तब तक शिमला में ही रहे।

ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी व सहप्रभारी आलाकमान तक सही रिपोर्ट दे पाएंगे या उन्हें मैनेज कर लिया जाएगा। बहरहाल, अब आखिरी चुनाव विधानसभा का बचा है, जो इस साल के आखिर में होना है। लगता है कि वीरभद्र सिंह व सुखविंदर सिंह सुक्खू की जोड़ी इस चुनाव को भी हरा कर ही अपने कुर्सियों से हटेंगे। संभवत: आलकमान उसी के बाद कुछ कदम उठा पाएंगी।

हिमाचल कौशल विकास निगम देगा 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षण

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम आगामी तीन सालों में प्रदेश के 50 हजार युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिसमें से वर्ष 2017–18 में 28 हजार युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं, जिसके लिए एडीबी द्वारा 640 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को भारत सरकार की स्वीकृति मिल गई है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मण्डल की चौथी बैठक में दी गई।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली तथा उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के अधिकतम युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न पाठयक्रमों में 1080 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा इसमें से 80 प्रतिशत युवाओं को 10 हजार रुपये की मासिक आय की औसत से संबंधित उद्योग व क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2017 में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में व्यवसाय में स्नातक एवं 'ग्रेजुऐट एड ऑन कार्यक्रम' लागू किए जाएंगे, जिससे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि शिमला के समीप तारादेवी में बनने वाले 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस' के लिए निगम को भूमि हस्तांतरित कर दी गई है तथा 20 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने अधिकारियों से सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने को कहा।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भाग–दो के अंतर्गत 14 हजार युवाओं को विभिन्न पाठयक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा बैठक की कार्यकारिणी का संचालन किया।

योग सामान्य पाठयक्रम में शामिल किया जाएगा:धूमल

सुजानपुर/शैल। दुनिया भर में योग का डंका पीटने का श्रेय बेशक योग गुरू बाबा राम देव को है लेकिन उनकी हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से नहीं बनती। बताते हैं कि कोई जमीन का झगड़ा हुआ था। तब से बाबा को धूमल वैसे ही अच्छे नहीं लगते जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल भाजपा के दूसरे बड़े नेता शांता कुमार अखरते रहते हैं। चूंकि मामला इंटरनेशनल योग डे का था तो बिना बाबा के काम तो चल नहीं सकता था ऐसे में दूसरे बाबा का इंतजाम किया गया और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को सुजानपुर बुलाया गया। उसके बाद वो धर्मशाला भी गए।

राजधानी शिमला में जब आर्टऑफ लिविंग की प्रेस कांफ्रेंस हुई थी तो कहा गया था कि श्री श्री रविशंकर धर्मशाला में ही जाएंगे। लेकिन वो सुजानपुर भी पहुंचे। साथ में मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री व छोटे परदे की अदाकारा स्मृति ईरानी ने योग डे पर सेलिब्रिटी का छौंक भी लगाया।

सुजानपुर में इंटरनेशनल योगा–डे पर ऐतिहासिक होली ग्राउंड में स्कूली छात्रों को बारिश में एक घंटे से ज्यादा श्री श्री रविशंकर और अन्य गणमान्यों के इंतजार में बैठे रहना पड़ा। इन नन्हे होनहारों को इस योग उत्सव में प्रतिभागी बनाने के लिए या फिर यूं कहे इस आयोजन को सफल दिखाने के लिए इकट्ठा किया गया था।

इस आयोजन को सफल बनाने के लिए खुद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, मंच का संचालन करते रहे। मुख्यतिथि श्री श्री रविशंकर के अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय कंपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस मौके पर शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, सांसद अनुराग ठाकुर,बीजेपी प्रदेश प्रभारी मंगल पांडेय ने योगासन किए।

वहीं स्थानीय लोगों को इस आयोजन के पीछे राजनीति भी छिपी हुई नजर आई। उनका कहना है कि इसके आयोजन करने के पीछे आगामी विधानसभा चुनावों का आना भी है, ताकि जनता के साथ जुड़ाव दिखाया जा सके। छात्रों के साथ आए कई अध्यापकों ने दबी जुबान में कहा कि इससे प्रकार की गतिविधियां रोजाना स्कूलों में की जाती हैं और इस प्रकार के विशेष आयोजन बच्चों की पढ़ाई पर असर डालते हैं। साथ ही मौसम के अनुकूल ना होने के वजह से बच्चों की तबीयत खराब होने का भी खतरा मंडराता रहता है।

वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने इस मौके पर उपस्थित स्कूली छात्रों के हौसला आफजाई करते हुए कहा कि योग कर रहे बच्चों को इसका जरूर फल मिलेगा। अब देखना होगा कि फल बच्चों को मिलता है या फिर इसके पीछे छिपे राजनेताओं को।

इस मौके पर धूमल ने कहा कि योग बौद्धिक और शारीरिक विकास को बढ़ाता है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा एलान भी कर दिया व कहा कि अगर आगामी चुनावों ने भाजपा प्रदेश में सरकार बनाती है तो योग को समान्य पाठयक्रम के रूप में शामिल किया जाएगा।

अपने संबोधन में स्मृति इरानी ने कहा कि योग भारत की संस्कृति और प्रकृति का प्रतीक है। इससे सदियों से हमें एकता और अनुशासन में रखा है।

निजी संस्थानों के स्टिकर लगाकर बेचे जा रहे प्रोस्पेक्टस

कांगड़ा/शैल। हमीरपुर स्नातकोतर महाविद्यालय में चल रही एडमिशन के दौरान न केवल छात्र शिक्षा के बहाने अपनी छात्र राजनीति को चमकाने को लगे हुए है बल्कि एक साथ सैंकड़ों प्रोस्पैक्टस खरीद कर निजी संस्थानों के स्टिकर लगाकर नए छात्रों को बेचकर उनका विज्ञापन भी करने में लगे हुए हैं।

सरकारी महाविद्यालय के एडमीशन प्रोस्पैक्टस पर छात्र राजनीति से जुड़े संगठन का नाम को भी भुनाया जा रहा है। इस तरह पच्चास रूपए के प्रोस्पैक्टस पर लाखों रूपए का विज्ञापन किया जा रहा है। हैरानी ये है कि ये सब कालेज परिसर में हो रहा है और कालेज प्रशासन जानबूज कर आंख बंद कर नए आ रहे छात्रों को एक तरह से दिशाविहिन होने में सहायक भी लगता नजर आ रहा है।

कुछ छात्र संगठन निजी संस्थानों से अपने संगठन के नाम को स्पांसर करवा कर एक ही स्टिकर पर उस संस्थान के नाम को भी प्रमोट करते दिख रहे हैं। छात्र राजनीति का दबदबा बनाकर कालेज के कांउंटर से ऐसे छात्र नेता एक साथ सैंकड़ों प्रोस्पैक्टस खरीद कर उन पर अपने नाम के ऐसे स्टिकर चिपका दे रहे हैं। कालेज प्रशासन की तरफ से पुराने छात्रों को एक कमरा दिया होता है जहां से वे केवल नए आने वाले छात्रों को किसी कांउटर या कमरे की जानकारी देने के लिए अधिकृत किया गया है, लेकिन ये छात्र इससे उल्टा कार्य कर नियमों की धज्जियां कालेज प्रशासन के सामने ही उड़ा रहे हैं। इससे नए छात्रों को पढ़ाई करने के बजाए किस निजी संस्थान में कोचिंग लेनी है और कालेज में आते ही किस बैनर तले राजनीति करनी है इसके बारे ही प्रोस्पैक्टस पर स्टिकर चिपका कर एवं मौखिक तौर पर भी यही समझाया जा रहा है। हैरानी यह है कि कालेज में एडमीशन प्रोस्पैक्टस बेचने का कांउटर एक साथ सैंकड़ों प्रोस्पैक्टस दो चार छात्रों को बेच देने पर इस अनियम कड़ी का हिस्सा बनते दिख रहा है। अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि अब तक कालेज के काउंटर से 3900 प्रोस्पैक्टस बिक चुके हैं और एडमीशन अब तक केवल 1100 ही हो पाई है। मंगलवार के दिन भी 900 के करीब एडमीशन प्रोस्पैक्टस बेचे गए और 420 एडमीशन हो पाई। संभवत: ऐसे छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने अपने लिए अधिक मात्रा में प्रोस्पैक्टस खरीद लिए और अब उन्हें अपने कब्जे में रख कर अपने तरीके से उन्हें आगे बेचा जा रहा है।

कालेज प्रिंसिपल डाक्टर हरदेव सिंह जम्वाल ने बताया कि कुछ छात्रें को केवल किसी कमरे या काउंउटर का पता न लगने पर केवल गाईड करने को बिठाया होता है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो गल्त हो रहा है। इस पर तुरंत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार
5 वाँ साल
उपलब्धियाँ बेमिसाल

हिमाचल प्रदेश में
मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के
दूरदर्शी मार्गदर्शन में
विकास और खुशहाली का 5वां साल

- **मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना**
  के तहत सौर ऊर्जा बाड़ के लिये उपदान राशि 60% से बढ़ाकर 80% की
- **कृषि के लिये ट्रेक्टर खरीदने पर**
  टैक्स एकमुश्त जमा करवाने की सुविधा
- **मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस परिवर्द्धन योजना**
  के तहत 5 वर्ष पश्चात् अथवा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त पॉलीशीट्स बदलने के लिये 50% उपदान
- **मुख्यमंत्री कृषि प्रोत्साहन योजना**
  के तहत निजी व सरकारी नर्सरियों में किवी फल पौधे एवं लोहे के एंगल पर 50% उपदान

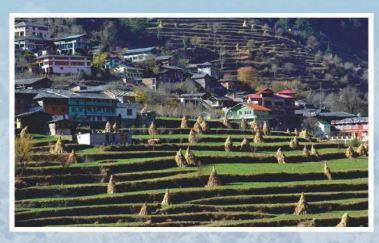

कृषि-बागवानी गतिविधियों के लिये आवंटित राशि
778 करोड़ रु. (2016-17) → 908 करोड़ रु. (2017-18)

खेतों में उगती - खुशहाली की फसलें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

14 अगस्त तक करना होगा 1950 से लेकर अब तक के भू-लेखों का डिजिटलाईज़ेशन

शिमला/शैल। मोदी सरकार ने नोटबंदी से पहले बेनामी संपत्तियों की स्वेच्छा से घोषणा करने के लिये लोगों को करीब एक वर्ष का समय दिया था। इस घोषणा की समय सीमा समाप्त होने के बाद नोटबंदी के तहत पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों का चलन बंद कर दिया था। सरकार के यह दानों फैसले काले धन के खिलाफ बड़ी कारवाई करार दिये गये थे। क्योंकि यह माना जाता है कि काले धन का निवेश व्यक्ति सामान्यत: चल/अचल संपत्ति खरीदने में करता है। यदि संपत्ति में यह निवेश नहीं है तो फिर पांच सौ और एक हजार के नोटों में ही इसका संग्रह करेगा। लेकिन बेनामी संपत्ति की घोषणा और उसके बाद नोटबंदी के आने से भी काले धन के संद्धर्भ में कोई विशेष परिणाम सामने नही आये हैं। इसलिये सारी भू-संपत्तियों की डिजिटलाईजेशन किये जाने और उसको आधार नम्बर से जोड़ने का फैसला लिया गया है।

15 जून को देश के सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/अतिरिक्त मुख्य सचिवों को सारे भू-अभिलेखों को 14 अगस्त तक डिजिटलाईज़ और आधार से लिंक करने के आदेश जारी किये गये है। क्योंकि हर भू -संपत्ति का राजस्व में रिकार्ड उपलब्ध रहता है। हर भू-संपत्ति का राजस्व रिकार्ड में कोई न कोई मालिक होना आवश्यक है। जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं है उसकी मालिक सरकार होती है। भू-संपत्ति अर्जित भी व्यक्ति दो ही प्रकार से करता है, या तो खरीद कर उसका मालिक बनता है या फिर पुश्तैनी रूप से उसे मिलती है। ऐसे में जो संपत्ति व्यक्ति के राजस्व रिकार्ड में होगी उसी का उसे मालिक माना जायेगा। इस डिजिटलाईजेशन के लिये 1950 को आधार वर्ष माना गया है क्योंकि 1947 में देश की आजादी और बंटवारे के बाद सारी स्थितियां सामान्य हो गयी थी और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ था। इसलिये व्यक्ति को उसकी वंश परम्परा से कब क्या मिला और उसने अपने स्तर पर कब क्या खरीदा इसका रिकार्ड राजस्व अभिलेख में होना आवश्यक है।

केन्द्र सरकार के आदेश के मुताबिक 1950 से लेकर अब तक सारे भू-अभिलेख म्यूटेशन और खरीद- बेच जिसमें कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य, मकान, प्लॉट व्यक्तिगत या सोसायटी के माध्यम से हासिल किया गया है सबका डिजिटलाईजेशन 14 अगस्त तक पूरा किया जाता है। जो संपत्तियां आधार नम्बर से लिंक नहीं होगी उन्हे बेनामी संपत्ति मानकर उसके खिलाफ आयकर अधिनियम 1861 की धारा दो तथा बेनामी संपत्ति संशोधित अधिनियम 2016 के तहत कारवाई की जीयेगी। केन्द्र सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिये केवल दो माह का समय दिया है। ऐसे में स्पष्ट है कि हर पटवारखाने को कम्प्यूटर से लैस करना होगा। हर पटवारी को कम्प्यूटरका प्रशिक्षण देना होगा। सारे भू-रिकार्ड को 1950 से लेकर अब तक उसकी डाटा एंट्री करनी होगी। क्या सरकार इस काम को दो माह के समय में पूरा कर पायेगी? क्योंकि प्रदेश के कई पटवारखानों में पटवारी तैनात ही नहीं है। कई जगह एक-एक पटवारी को दो-दो पटवारखानों का काम सौंपा हुआ है।

इस समय विभाग में पटवारीयों के 2565 पद सृजित है और 2338 पटवार वृत हैं जिनमें 397 कानूनगो सेवायें दे रहे हैं। विभाग में करीब 2400 पटवारी काम कर रहे हैं। सरकार ने भू -अभिलेखों को डिजिटल करने का काम पिछले एक दशक से शुरू कर रखा है। पटवारीयों को इस काम को अन्जाम देने के लिये लैपटॉप भी उपलब्ध करवा रखे हैं। लेकिन अभी तक एक दशक में करीब वर्षो के रिकार्ड को ही डिजिटल किया जा सका है और इसको भी आधार से लिंक नही किया गया है। अब केन्द्र सरकार ने 1950 से लेकर अब तक के रिकार्ड डिजिटलाईज़ करके आधार से लिंक करने के आदेश किये हैं। केन्द्र का यह आदेश अभी तक निदेशक लैण्ड रिकार्ड तक नही पहुंचा है। लेकिन इसमें विभाग के सामने संभवत: कई कठिनाईयां आ सकती है कि 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद पंजाब के जो भाग हिमाचल में मिले हैं जिनमें वर्तमान कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लु और शिमला के कुछ भाग आते हैं इनका 1966 से पहले का लैण्ड रिकार्ड आज यहां उपलब्ध होगा या नहीं। यदि यह रिकार्ड उपलब्ध न हुआ तो क्या इसे पंजाब से हासिल किया जायेगा। विभाग ने संभवत: इस पक्ष पर अभी तक विचार ही नहीं किया है। ऐसे में भारत सरकार के आदेश की 14 अगस्त तक पूरी तरह से अनुपालना हो पाना संभव नहीं लग रहा है।

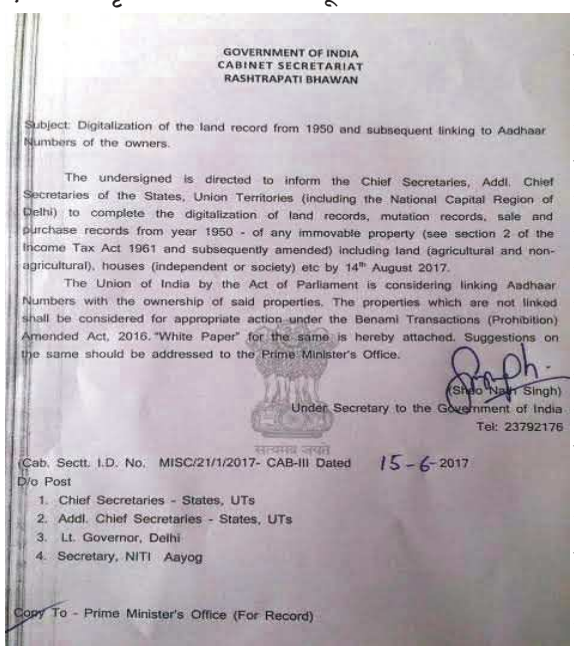

GOVERNMENT OF INDIA
CABINET SECRETARIAT
RASHTRAPATI BHAWAN

Subject: Digitalization of the land record from 1950 and subsequent linking to Aadhaar Numbers of the owners.

The undersigned is directed to inform the Chief Secretaries, Addl. Chief Secretaries of the States, Union Territories (including the National Capital Region of Delhi) to complete the digitalization of land records, mutation records, sale and purchase records from year 1950 - of any immovable property (see section 2 of the Income Tax Act 1961 and subsequently amended) including land (agricultural and non-agricultural), houses (independent or society) etc by 14th August 2017.

The Union of India by the Act of Parliament is considering linking Aadhaar Numbers with the ownership of said properties. The properties which are not linked shall be considered for appropriate action under the Benami Transactions (Prohibition) Amended Act, 2016. "White Paper" for the same is hereby attached. Suggestions on the same should be addressed to the Prime Minister's Office.

(Shalini Nath Singh)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23792176

(Cab. Sectt. I.D. No. MISC/21/1/2017- CAB-III Dated 15-6-2017
D/o Post
1. Chief Secretaries - States, UTs
2. Addl. Chief Secretaries - States, UTs
3. Lt. Governor, Delhi
4. Secretary, NITI Aayog

Copy To - Prime Minister's Office (For Record)

क्या अधिकारियों के आपसी हितों के टकराव का परिणाम है 14 करोड़ का सब्सिडी प्रकरण

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश का बागवानी विभाग इन दिनों अचानक चर्चाओं का केन्द्र बन गया है, क्योंकि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2010-11 में स्थापित की गयी एंटीहेल गन खरीद को लेकर विजिलैन्स विभाग ने अब एक एफआईआर दर्ज की है। मिशन निदेशक और हेलगन स्पलाई करने वाली कंपनी ग्लोबल एवियेशन हैदराबाद के नाम यह मामला दर्ज हुआ है। जब से यह हेलगन स्थापित हुई है तभी से संबंधित क्षेत्र के बागवान इसके परिणामों से सन्तुष्ट नहीं रहे है। इस खरीद की जांच किये जाने की मांग तभी से उठती आयी है। कांग्रेस के आरोप पत्र में भी इस मामले को उठाया है लेकिन इस मामले में एफआईआर अब नगर निगम चुनावों के बाद हुई है। स्मरणीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2008- 09 में प्रदेश सरकार को इसके लिये 80 लाख रूपये दिये थे। इसके बाद वर्ष 2009 -10 में 2.80 लाख रूपया प्रदेश को दिया और इस तरह तीन करोड़ में से 2.89 करोड़ में ग्लोबल एवियेशन से हेलगन की खरीद हो गयी। इस पूरे प्रकरण की प्रक्रिया सचिवालय और सरकार के स्तर पर ही अंजाम में लायी गयी है। इसलिये विजिलैन्स की जांच इस संद्धर्भ में तत्कालीन बागवानी मन्त्री और सचिव तक अवश्य आयेगी। इस हेलगन के आप्रेशन के लिये संभवत: रक्षा मन्त्रालय से भी अनुमति ली जानी थी जो कि शायद नही ली गयी है।

हेलगन प्रकरण अभी शान्त भी नही हुआ था कि ठियोग के बलघार में बने कोल्डस्टोर के लिये दी गयी 14 करोड़ की सब्सिडी पर सवाल उठ गये। मुख्यमन्त्री ने भी इस प्रकरण में जांच करवाये जाने की बात की है। मजे की बात यह है बागवानी विभाग के परियोजना निदेशक डा. प्रदीप सांख्यान जिन्होने यह सब्सिडी जारी की है उन्होने भी इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बलघार में यह कोल्डस्टोर भारत सरकार की 50: उपदान योजना के तहत 2015-16 में स्थापति हुआ है। 28 करोड़ के निवेश का यह कोल्डस्टोर एक हिम एग्रो फ्रैश ने स्थापित किया है। केन्द्र सरकार में यह प्रौजैक्ट 20.7.2015 को स्वीकृत हुआ और फिर इसके निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसका निर्माण शुरू होने के बाद विभाग की पहली संयुक्त निरीक्षण कमेटी ने 11.7.2016 को इसका निरीक्षण किया। इस कमेटी का गठन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण श्रीधर द्वारा किया गया था। परियोजना निदेशक, वरिष्ठ मार्किटिंग अधिकारी, फूट टैक्नौलोजिस्ट, विषय विशेषज्ञ, बैंकर और कोल्डस्टोर स्थापित करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि इस निरीक्षण कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद कंपनी को तब तक हुए काम और निवेश के आधार पर 3.8.2016 को 20 लाख की सब्सिडी रिलिज कर दी जबकि 25.93 लाख दी जानी थी। 5.93 लाख इसलिये नहीं दी गयी कि विभाग के पास पैसा ही नही था। इस निरीक्षण कमेटी ने मौके पर हुए काम के बारे में पूरा सन्तोष व्यक्त किया है।

इस पहली निरीक्षण के बाद विभाग के निदेशक डा. बवेजा स्वयं 10.3.2017 को इस कोल्डस्टोर को देखने गये। इसी बीच विभाग को केन्द्र से इसकी सब्सिडी के 11 करोड़ मिल जाते हैं और 23.3.2017 को विभाग इस पैसे को ड्रा कर लेता है। यह पैसा आने के बाद कंपनी को 5.93 लाख की पैमैन्ट कर दी जाती है जो पहले नही हो पायी थी। जब निदेशक डा. बवेजा इसके निरीक्षण के लिये गये तो उन्होने इसके निर्माण आदि पर कोई सवाल खडे नहीं किये। बल्कि 29.4.17 को अपनी रिपोर्ट में केवल यह कहा कि निरीक्षण टीम में कुछ और विशेषज्ञ शामिल कर लिये जायें। निदेशक के इस सुझाव पर एसएलईसी की फिर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें पहली कमेटी में एचपीएमसी के रैफरिजेटर इंजिनियर डीजीएम और नौणी विश्वविद्यालय के प्रौफैसर को भी शामिल कर लिया विभाग के प्रधान सचिव जेसी शर्मा ने 22.5.17 को यह दूसरी संयुक्त निरीक्षण टीम का गठन कर दिया। इसी टीम ने 26.5.2017 को कोल्डस्टोर का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट उसी दिन सौंप दी। यह रिपोर्ट मिलने के बाद 27.5.17 को ही सब्सिडी का सारा शेष पैसा कंपनी को रिलीज कर दिया गया। जब यह दूसरी निरीक्षण टीम गठित हुई निरीक्षण पर की गयी, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट के दूसरे ही दिन सब्सिडी रिलिज कर दी गयी। इस पूरी प्रक्रिया में पांच दिन का समय लगा। 22.5.17 को यह प्रक्रिया शुरू होती है और 27.5.17 को पेमैन्ट के साथ पूरी हो जाती है। सब्सिडी रिलिज करने के लिये कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील कंवर जीत सिंह के माध्यम से विभाग को एक नोटिस भी जारी किया था।

इस पूरे प्रकरण में यह सवाल उठाया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया केवल पांच दिन में ही क्यों पूरी कर गयी? इस दौरान विभाग के निदेशक संभवत: विदेश दौरे पर थे और यह सारी प्रक्रिया प्रधान सचिव जेसी शर्मा के आदेशों से पूरी हुई है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि पहली जेआईटी केन्द्र की गाईडलाईनज़ पर विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण श्रीधर के आदेशों पर गठित हुई थी। इस जेआईटी में निदेशक बवेजा ने कुछ और विशेषज्ञ शामिल करने का सुझाव दिया? क्या उनकी नजर में पहली जेआईटी सक्षम नही थी? बवेजा के निर्देशों पर दूसरी जेआईटी गठित होती है और उसमें तीन नये लोग शामिल कर लिये जाते हैं। क्या बवेजा के निर्देशों पर दूसरी जेआईटी में तीन नये विशेषज्ञ शामिल किये जाने आवश्यक थे? यदि यह आवश्यक थे और उन्हे शामिल भी कर लिया गया तो क्या इस दूसरी जेआईटी की रिपोर्ट भी बवेजा के समाने नही रखी जानी चाहिये थी? क्या निरीक्षण टीम के सदस्यों की योग्यता पर दोनों बार डा. बवेजा को सन्देह था या फिर उनकी मंशा कुछ और थी? यदि मुख्यमन्त्री वास्तव में इसकी जांच करवाते हैं तभी इन सारे सवालों का खुलासा हो पायेगा। वैसे इस प्रकरण के इस तरह चर्चा में आने से भविष्य में कोई भी निवेश करने के लिये आगे नही आयेगा।

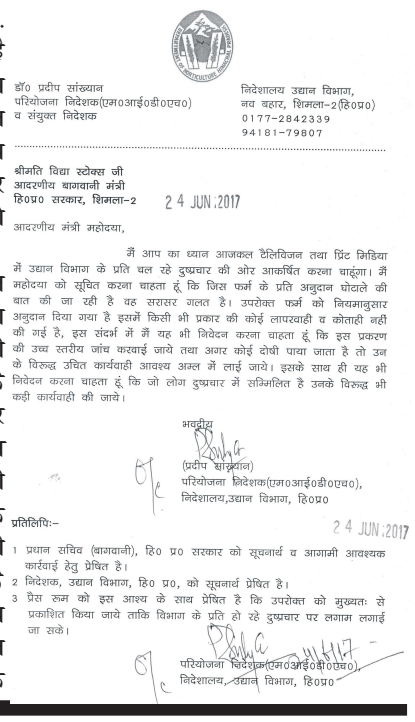

डॉ० प्रदीप सांख्यान
परियोजना निदेशक(एम0आई0डी0एच0)
व संयुक्त निदेशक

निदेशालय उद्यान विभाग,
नव बहार, शिमला-2(हि0प्र0)
0177-2842339
94181-79807

श्रीमति विद्या स्टोक्स जी
आदरणीय बागवानी मंत्री
हि0प्र0 सरकार, शिमला-2

24 JUN 2017

आदरणीय मंत्री महोदया,

मैं आप का ध्यान आजकल टैलिविजन तथा प्रिंट मिडिया में उद्यान विभाग के प्रति चल रहे दुष्प्रचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं महोदया को सूचित करना चाहता हूं कि जिस फर्म के प्रति अनुदान घोटाले की बात की जा रही है वह सरासर गलत है। उपरोक्त फर्ज को नियमानुसार अनुदान दिया गया है इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही व कोताही नहीं की गई है, इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये तथा अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन के विरूद्ध उचित कार्यवाही आवश्य अक्ल में लाई जाये। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग दुष्प्रचार में सम्मिलित है उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाये।

भवदीय
(प्रदीप सांख्यान)
परियोजना निदेशक(एम0आई0डी0एच0),
निदेशालय,उद्यान विभाग, हि0प्र0

प्रतिलिपि:-
24 JUN 2017
1 प्रधान सचिव (बागवानी), हि0 प्र0 सरकार को सूचनार्थ व आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
2 निदेशक, उद्यान विभाग, हि0 प्र0, को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 प्रैस रूम को इस आश्य के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त को मुख्यतः से प्रकाशित किया जाये ताकि विभाग के प्रति हो रहे दुष्प्रचार पर लगाम लगाई जा सके।

परियोजना निदेशक(एम0आई0डी0एच0),
निदेशालय, उद्यान विभाग, हि0प्र0